अव्यवस्था जनरेटर और सीसीटीवी बंद, तहसीलदार के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली उजागर

मेहंदवानी सीएचसी में मरीजों की जान से खिलवाड़

शहपुरा नवभारत 14 जून। ग्रामीण अंचल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के सरकारी दावे मेहंदवानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं।

शनिवार को तहसीलदार तेजी लाल के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। अस्पताल में महीनों से जनरेटर बंद पड़ा मिला, वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी निष्क्रिय पाए गए। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद तहसीलदार अचानक अस्पताल पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई।

नवजात बच्चे भीषण गर्मी में परेशान होते रहे

अस्पताल में बिजली कटौती के दौरान मरीजों को राहत देने वाला जनरेटर बंद मिला, जिससे वार्डों में भर्ती मरीज, प्रसूताएं और नवजात बच्चे भीषण गर्मी में परेशान होते रहे। हैरत की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने इस गंभीर समस्या के समाधान की कोई कोशिश तक नहीं की। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि अस्पताल परिसर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से बंद पड़े हैं। ऐसे में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है।

जिम्मेदारों की लापरवाही पर बरसे तहसीलदार

अस्पताल की बदहाल स्थिति देखकर तहसीलदार तेजी लाल ने मौके पर मौजूद खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. रणमत परस्ते एवं संबंधित कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बंद पड़े जनरेटर एवं सीसीटीवी कैमरों को तत्काल चालू कराया जाए तथा पेयजल सहित अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को शीघ्र दुरुस्त किया जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय करने की चेतावनी भी दी।

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल में जनरेटर और सीसीटीवी जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं लंबे समय से बंद थीं, तब जिम्मेदार अधिकारियों ने इसकी सुध क्यों नहीं ली? क्या स्वास्थ्य विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था? ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया, जिससे विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं।

बिना लाइसेंस बीज बेच रहे व्यापारी की दुकान सील

कृषि विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

डिंडोरी, नवभारत 14 जून। खरीफ वर्ष 2026 को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग द्वारा जिले में खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रय केंद्रों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उपसंचालक कृषि एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी संजय दोशी के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय निगरानी दल एवं विकासखंड स्तरीय निरीक्षण दल लगातार औचक निरीक्षण एवं छापामार कार्रवाई कर रहे हैं।

इसी क्रम में कृषि विभाग की टीम ने अमरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सक्का में संचालित निजी प्रतिष्ठान अबिंका ट्रेडर्स का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा बिना वैध लाइसेंस के बीज का विक्रय किया जा रहा था। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर गठित दल ने मौके पर उपलब्ध बीज का जप्ती पंचनामा तैयार किया तथा कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया।

अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई

निरीक्षण दल द्वारा कृषि साख सहकारी समिति सक्का एवं अमरपुर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

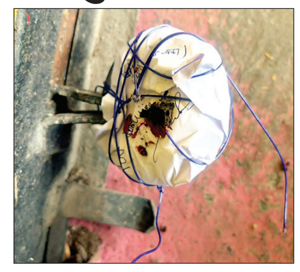

अभियान लगातार जारी रहेगा

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित कृषि आदान सामग्री उपलब्ध कराने तथा अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया जिला अध्यक्ष संजय दुबे का इस्तीफा

कांग्रेस में बड़ा भूचाल, संगठन पर उठे कई सवाल

शहपुरा नवभारत 14 जून। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष और गुटबाजी की चर्चाओं के बीच डिंडोरी जिले से एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग डिंडोरी के जिला अध्यक्ष संजय दुबे ने अपने पद से इस्तीफा देकर जिले की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।

संजय दुबे के इस्तीफे के बाद कांग्रेस संगठन के भीतर नेतृत्व, कार्यशैली और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 13 जून 2026 को प्रदेश सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष चंचलेश व्यास को संबोधित अपने त्यागपत्र में संजय दुबे ने पारिवारिक दायित्वों, व्यावसायिक व्यस्तताओं एवं व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है।

वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को लेकर असंतोष

उन्होंने लिखा है कि वे संगठन को अपेक्षित समय और पूर्ण समर्पण नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए पद छोड़ना उचित समझते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस इस्तीफे को केवल व्यक्तिगत कारणों तक सीमित नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि हाल ही में हुए मीनाक्षी नटराजन प्रकरण और युवा कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा है।

संगठन के भीतर बन रहे हालात से थे असहज

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता माने जाने वाले संजय दुबे भी संगठन के भीतर बन रहे हालात से असहज थे। हालांकि उनके आधिकारिक त्यागपत्र में किसी नेता का नाम नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे संगठन के भीतर पनप रहे असंतोष का संकेत माना जा रहा है।

संगठन में बढ़ी हलचल

संजय दुबे लंबे समय से कांग्रेस के सोशल मीडिया और संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में उनके इस्तीफे को कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस संगठन की ओर से इस इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, भूपेंद्र मरावी की ओर से भी इस पूरे घटनाक्रम पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है।

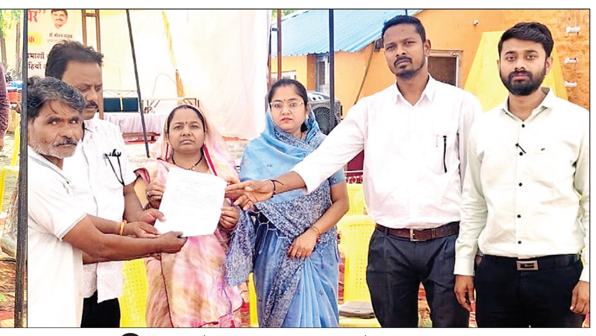

27 हितग्राहियों को मिला शासन की योजनाओं का लाभ

जन कल्याण शिविर का सफल समापन

डिंडोरी, नवभारत 14 जून। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देशन में नगर परिषद डिंडोरी परिसर में 12 से 14 जून तक आयोजित जन कल्याण शिविर का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ।

समापन अवसर पर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हितलाभ एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के 12, नवीन नल कनेक्शन के 6, पीएम स्वनिधि योजना के 6, पात्रता पर्ची के 2 तथा संबल अनुग्रह सहायता योजना के 1 हितग्राही को लाभ प्रदान किया गया। इस प्रकार कुल 27 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

योजनाओं का लाभ लेने की अपील

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शासन द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना तथा पात्र हितग्राहियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने नागरिकों से शासन की जनहितकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। तीन दिवसीय शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

ई-रिक्शा के माध्यम से निकाली गई स्वागत रैली

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार का शहडोल में स्वागत

शहडोल। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार के प्रथम शहडोल नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विनय केवट ने बताया कि नव नियुक्त जिला अध्यक्ष राकेश कनौजिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता जय स्तंभ चौक पर एकत्रित हुए और श्री पाटीदार का पुष्पमालाओं, पुष्पगुच्छ, आतिशबाजी तथा ढोल-नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया।

स्वागत कार्यक्रम के बाद श्री पाटीदार कार्यकर्ताओं के साथ ई-रिक्शा में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत, प्रदूषण नियंत्रण एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील को व्यवहार में उतारते हुए ई-रिक्शा से यात्रा कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके पश्चात भाजपा कार्यालय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जिला बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने संगठन की मजबूती, केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने तथा आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष अमिता चपरा ने की, जबकि स्वागत उद्बोधन पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष राकेश कनौजिया ने दिया। कार्यक्रम में विधायक मनीषा सिंह, जैतपुर विधायक जयसिंह मरावी, ब्यौहारी विधायक शरद कोल, अमरकंटक विकास प्राधिकरण अध्यक्ष राजेंद्र भारती, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम पटेल, राव उदय प्रताप सिंह, संभागीय प्रभारी सुशील राय, प्रदेश सह-कोषाध्यक्ष शक्ति लक्षकार, उपाध्यक्ष संतोष लोहानी, मनोज गुप्ता, जिला महामंत्री अमित मिश्रा, पुष्पेन्द्र पटेल, जिला मंत्री रविन्द्र वर्मा, पूर्व अध्यक्ष रमाशंकर कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष राकेश कन्नौजिया पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष महेश सराफसहित भाजपा एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एसईसीएल में 21 भू-आश्रितों को मिला रोजगार का नया अवसर

बेलिया, खैरहा, खांडा, कंदोहा और रामपुर के युवाओं को मिली नौकरी

नवभारत, धनपुरी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के सोहागपुर क्षेत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को 21 भू-आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। महाप्रबंधक कार्यालय, सोहागपुर क्षेत्र के सभागार में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया। इस पहल को प्रभावित परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सोहागपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक बी के जेना ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नियुक्ति

प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी उन परिवारों से संबंधित हैं जिनकी भूमि एसईसीएल की विभिन्न खनन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई थी। कंपनी की पुनर्वास एवं रोजगार नीति के तहत इन भू-आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

जानकारी के अनुसार नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ग्राम बेलिया, खैरहा, खांडा, कंदोहा और रामपुर के निवासी हैं। इन युवाओं को कंपनी की स्वीकृत रिक्तियों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में पदस्थ किया गया है। नियुक्त कर्मचारियों को सोहागपुर, जोहिला और हसदेव क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कार्यभार सौंपा जाएगा। इससे न केवल प्रभावित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि कंपनी और स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि एसईसीएल परियोजना प्रभावित परिवारों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि रोजगार प्रदान करना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने नव-नियुक्त कर्मचारियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे कंपनी की कार्यसंस्कृति, सुरक्षा मानकों और अनुशासन का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। कार्यक्रम में वितरित किए गए कुल 21 नियुक्ति पत्रों में से 11 नियुक्तियां राजेन्द्र-खैरहा उपक्षेत्र से संबंधित भू-आश्रितों को प्रदान की गईं, जबकि 10 नियुक्तियां रामपुर-बटूरा उपक्षेत्र के प्रभावित परिवारों के सदस्यों को मिलीं। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला। कई परिवारों ने इसे अपने जीवन में नई शुरुआत और आर्थिक स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर बताया। इस अवसर पर क्षेत्र के महाप्रबंधक (संचालन), मनीष श्रीवास्तव उपक्षेत्रीय पी हरी बाबू प्रबंधक राजेन्द्र-खैरहा उपक्षेत्र, स्टाफ ऑफिसर (एचआर), विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सभी नव-नियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं और बधाई देने के साथ हुआ।

एसईसीएल की इस पहल को क्षेत्र में परियोजना प्रभावित परिवारों के प्रति कंपनी की सकारात्मक सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे प्रभावित परिवारों को रोजगार के माध्यम से सम्मानजनक जीवनयापन का अवसर प्राप्त होगा और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी।

फुटबॉल का महाकुंभ चयनकर्ताओं ने सराही शहडोल की प्रतिभा, जिला फुटबॉल संघ ने खिलाड़ियों के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि घोषित की

ट्रायल में पहले दिन 445 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

शहडोल, नवभारत। जिले के मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध ग्राम विचारपुर स्थित स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल मैदान में शनिवार से मध्य प्रदेश फुटबॉल अकादमी के तीन दिवसीय मेगा चयन ट्रायल का भव्य शुभारंभ हुआ। 13 से 15 जून तक आयोजित इस ट्रायल के पहले ही दिन 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 445 बालक-बालिकाओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित अतिथियों एवं मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ से आए चयनकर्ताओं एवं प्रशिक्षकों का जिला फुटबॉल संघ शहडोल द्वारा शॉल, श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। ट्रायल के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के मुख्य चयनकर्ता एवं अनुभवी कोच स्वप्न कुमार विश्वास ने विचारपुर

की फुटबॉल संस्कृति और खिलाड़ियों की प्रतिभा की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर के भ्रमण के दौरान उन्हें शहडोल जैसी खेल प्रतिभा और ऊर्जा कहीं देखने को नहीं मिली। उन्होंने स्थानीय कोचों और जिला फुटबॉल संघ के प्रयासों को भी सराहते हुए विश्वास जताया कि भविष्य में इसी मैदान से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे।

जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छाबड़ा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में फुटबॉल के प्रति बढ़ता उत्साह सुखद संकेत है। उन्होंने खिलाड़ियों के विकास और प्रशिक्षण के लिए जिला फुटबॉल संघ की ओर से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संघ खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। ट्रायल का संचालन मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा नियुक्त प्रशिक्षक आशीष पिल्ले एवं स्वप्न कुमार विश्वास की देखरेख में किया जा रहा है। चयनित खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर का निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्रम में जिला फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष ए.के. मोहंती, सचिव रईस अहमद, कोषाध्यक्ष अनिल सिंह, रिलायंस फाउंडेशन से डॉ. समीम खान, वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी क्रेतराम सिंह, राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं कोच नीलेंद्र कुंडे सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, कोच और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

शिक्षकों के हित में एकजुटता ही सफलता की कुंजी : तिवारी

टीईटी से छूट की मांग को लेकर शिक्षकों का बड़ा अभियान, 18 को पीएम के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन

शहडोल। अभी नहीं तो कभी नहींहक की लड़ाई में कभी निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वे खुद-ब-खुद चले आते हैं तथा समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध जैसे प्रेरक आह्वानों के साथ मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) से छूट प्रदान करने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।

मध्य प्रदेश शिक्षक संघ शहडोल के जिला अध्यक्ष लालजी तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शिक्षक संघ के राष्ट्रीय संगठन अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर 18 जून 2026 को पूरे देश के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी एक साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन

सौंपा जाएगा। शहडोल में यह ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से सायं 5 बजे से 5रू15 बजे के बीच प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 29 मई 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है। न्यायालय के निर्णय का सम्मान सभी का संवैधानिक दायित्व है, किंतु इस निर्णय से देशभर के लगभग 20 लाख से अधिक शिक्षक एवं उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उनके समक्ष असमंजस और भविष्य की चिंता का गंभीर संकट खड़ा हो गया है ।शिक्षक संघ का कहना है कि इस विषय का समाधान विधायिका के माध्यम से संभव है। इसलिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए आगामी मानसून सत्र में विधेयक लाकर वर्ष 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से छूट प्रदान की जाए।

संघ ने जिले के सभी शिक्षकों से इस महत्वपूर्ण अभियान में सहभागिता करते हुए 18 जून को आयोजित ज्ञापन कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि शिक्षकों की वर्षों पुरानी सेवा एवं अनुभव को सम्मान दिलाने की दिशा में एक मजबूत और प्रभावी पहल की जा सके।